आकार IAS

Shaping Your Dreams

भारतीय अर्थव्यवस्था

मुख्य परीक्षा

प्रश्नपत्र-02 | भाग-02 | इकाई-01

160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com www.aakarias.com
9713300123, 6262856797, 6262856798

प्रश्न पत्र - 02

भारतीय अर्थव्यवस्था
INDIAN ECONOMY

भाग - 02
Part - 02

❐ इकाई - 1

- भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय।
- भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना।
- भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति।
- अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं - प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नकद लेन-देन, राजकोषीय नीति।
- लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन।
- भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेश पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, आयात-निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक।

❐ Unit - 1

- Introduction to Indian Economy.
- Issues and Initiatives in the field of Agriculture, Industry and Services Sector in India.
- Measurement of national income in India.
- Functions of Reserve Bank of India and Commercial Banks, Financial Inclusion, Monetary Policy.
- Characteristics of a good taxation system - Direct Taxes and Indirect Taxes, Subsidies, Cash Transactions, Fiscal Policy.
- Public Distribution System, current trends and challenges of the Indian economy, poverty, unemployment and regional imbalances.
- India's International Trade and Balance of Payments, Role of Foreign Capital, MNCs, Foreign Direct Investment, Import-Export Policy, International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, WTO, ASEAN, SAARC, NAFTA and OPEC.

परीक्षा योजना

सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग-II की इकाई-I का **पूर्णांक 30** है।

इकाई	प्रश्न	संख्या	x	अंक	=	कुल अंक	आदर्श शब्द सीमा
इकाई-1	अति लघु उत्तरीय	03	x	03	=	09	10 शब्द/01 पंक्ति
	लघु उत्तरीय	02	x	05	=	10	50 शब्द/05 से 06 पंक्तियां
	दीर्घ उत्तरीय	01	x	11	=	11	200 शब्द

नोट - प्रश्नों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी।

विषय सूची (CONTENTS)

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय अर्थव्यवस्था–एक परिचय	1 – 7
2.	कृषि	8 – 22
3.	भारत की औद्योगिक नीति एवं प्रमुख उद्योग	23 – 33
4.	लघु तथा कुटीर उद्योग	34 – 39
5.	भारत में सेवा क्षेत्र	40 – 42
6.	आत्मनिर्भर भारत	43 – 45
7.	भारत में राष्ट्रीय आय की गणना	46 – 56
8.	भारतीय वित्तीय प्रणाली	57 – 75
9.	भारतीय कर व्यवस्था	76 – 82
10.	सब्सिडी	83 – 90
11.	नकद लेन–देन	91 – 93
12.	राजकोषीय नीति	94 – 101
13.	खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	102 – 104
14.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	105 – 111
15.	भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां	112 – 115
16.	गरीबी	116 – 126
17.	बेरोजगारी	127 – 141
18.	क्षेत्रीय असंतुलन	142 – 147
19.	भारत का अंर्तराष्ट्रीय और भुगतान संतुलन	148 – 154
20.	भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियां	155 – 156
21.	विदेशी पूंजी की भूमिका	157 – 159
22.	बहुराष्ट्रीय कंपनियां	160 – 163
23.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	164 – 166
24.	आयात–निर्यात नीति	167 – 171
25.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – 1945	172 – 177
26.	विश्व बैंक समूह	178 – 183
27.	विश्व व्यापार संगठन	184 – 188
28.	एशियाई विकास बैंक	189 – 192
29.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – दक्षेस	193 – 196

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
30.	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन	197 – 200
31.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	201 – 203
32.	नाफ्टा	204 – 206

भारतीय अर्थव्यवस्था-एक परिचय
Introduction to Indian Economy

- अर्थव्यवस्था क्या है
- अर्थशास्त्र
  - अर्थशास्त्र की शाखाएं
    - व्यष्टि अर्थशास्त्र
    - समष्टि अर्थव्यवस्था
- अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण
  - सरकार की भूमिका के आधार पर
    - पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
    - समाजवादी अर्थव्यवस्था
    - मिश्रित अर्थव्यवस्था
    1) नियोजित अर्थव्यवस्था
    2) बाजार मिश्रित अर्थव्यवस्था
    3) उदारवादी अर्थव्यवस्था
  - पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अन्तर
  - विकास की अवस्था के आधार पर
    - विकसित
    - विकासशील
    - अल्पविकसित
  - विकास के आधार पर नवीन वर्गीकरण
    - निम्न आय
    - निम्न-मध्यम आय
    - उच्च-मध्य आय
    - उच्च आय
  - विश्व के साथ संबंधों के आधार पर
    - बंद
    - खुली
  - अन्य आधार
    - प्रथम विश्व के देश
    - द्वितीय विश्व के देश
    - तृतीय विश्व के देश
- आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण
  - प्राथमिक क्षेत्र
  - द्वितीयक क्षेत्र
  - तृतीयक क्षेत्र
  - चतुर्थक क्षेत्र
  - पंचक क्षेत्र
- उत्पादन के साधन
  - भूमि
  - श्रम
  - पूंजी
  - उद्यम/साहस

भारतीय अर्थव्यवस्था-एक परिचय
Introduction to Indian Economy

❒ अर्थव्यवस्था क्या है (What is Economy)

जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां आर्थिक गतिविधि किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा सीमित संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में किसी राष्ट्र द्वारा लोककल्याण के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ को केन्द्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है।

वस्तुतः यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या, कितना, कैसे एवं किसके लिए उत्पादन किया जाए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में बनाई गई व्यवहारिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, जब तक इसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र का नाम नहीं जोड़ा जाए, जैसे - भारत व चीनी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था आदि।

❒ अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है, जिससे हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। **एडम स्मिथ** को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है।

❖ अर्थशास्त्र की शाखाएं (Branches of Economics)

• व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे - एक व्यक्तिगत फर्म या उत्पादन गृह अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा उस उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है।

• समष्टि अर्थव्यवस्था (Macro Economics)

समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित किया जाता है। रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

❒ अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण (Types of Economy)

अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण

सरकार की भूमिका के आधार पर	विकास की अवस्था के आधार पर	विश्व के साथ संबंधों के आधार पर
- पूंजीवादी (Capitalist)	- विकसित (Developed)	- बंद (Closed)
- समाजवादी (Socialist)	- विकासशील (Developing)	- खुली (Open)
- मिश्रित (Mixed)	- अल्पविकसित (Under-Devoloping)	

❖ सरकार की भूमिका के आधार पर

• पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्रों व बाजार की भूमिका प्रभावकारी होती है। आर्थिक गतिविधियों के समस्त निर्णय जैसे – कितना उत्पादन किया जाए, किसका किया जाए एवं कैसे किया जाए, निजी क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों (मांग व पूर्ति) द्वारा संचालित होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरणार्थ – अमेरिका, कनाड़ा, मैक्सिको आदि।

• समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण व नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा होता है, इसलिए इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहां बाजार कारकों की भूमिका सीमित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां उपभोग उत्पादन का निर्धारण करता है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उपभोग का निर्धारण करता है। इसी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ से प्रेरित होती है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित होती है। उदाहरणार्थ – चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया आदि।

• मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

एक ऐसी प्रणाली, जिसमें बाजार यंत्र के संचालन के साथ राज्य की भूमिका भी साथ-साथ चले, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बुनियादी निर्णय राज्य द्वारा तथा गौण निर्णय बाजार द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ – भारत, नार्वे, स्वीडन आदि। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया है, जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं।

◆ नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy)

भारत में विकास के लिए आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई, जिसे कार्यान्वित करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है।

◆ बाजार मिश्रित अर्थव्यवस्था (Market Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस रूप में बाजार घटक मुख्य भूमिका में होता है तथा सरकार की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में गौण होती है।

◆ उदारवादी अर्थव्यवस्था (Liberal Economy)

इसमें उपरोक्त दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत द्वारा 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों के बाद उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई।

नोट – भारत में नव-आर्थिक सुधारों 1991 के बाद से उदारवादी व्यवस्था प्रचलित है।

❖ पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अन्तर

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था	समाजवादी अर्थव्यवस्था	मिश्रित अर्थव्यवस्था
• अहस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व	• संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व/ नियंत्रण	• संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व
• सामान्यत: अधिकतम लाभ अभिप्रेरित अर्थव्यवस्था	• सामान्यत: समाज कल्याण अभिप्रेरित अर्थव्यवस्था	• समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए लाभ अभिप्रेरित अर्थव्यवस्था

• मांग व आपूर्ति/बाजार की शक्तियां केंद्र में	• योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण	• बाजार और गैर-बाजार दोनों घटक एक साथ
	• उत्पादन और मूल्य पर सरकार का नियंत्रण	
	• निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं	
	• बाजार, बाजार की शक्तियां, मांग-आपूर्ति, प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित	
• प्रतियोगिता पर बल	• सामान्यत: प्रतियोगिता विहीन	• प्रतियोगिता एवं अपवादात्मक नियंत्रण
• अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको आदि।	• रूस, चीन, उ. कोरिया आदि।	• भारत, नार्वे आदि।

❖ विकास की अवस्था के आधार पर

- **विकसित (Developed)**

ऐसी अर्थव्यवस्था, जो औद्योगिक विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्थाएं अपने संसाधनों एवं अपनी विकास संभावनाओं का दोहन कर चुकी हैं। अत: अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए नवीन बाजारों की तलाश करती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। उदाहरण- अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि।

- **विकासशील (Developing)**

ऐसी अर्थव्यवस्था, जहां औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई है। इन अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा अब तक अपने संसाधनों व विकास संभावनाओं को अपेक्षित दोहन संभव नहीं हो सका है। यहां GDP में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा होता है व औद्योगिक व सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा होता है। उदाहरण- भारत, चीन, पाकिस्तान आदि।

- **अल्पविकसित (Under-Devoloping)**

ऐसी अर्थव्यवस्था, जो अपने विकास के आरंभिक चरण में है और जो अपने संसाधनों व विकास संभावनाओं का अभी भी दोहन नहीं कर पा रही है। यहां GDP में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अभी भी अहम है। उदाहरण- भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि।

❖ विकास के आधार पर नवीन वर्गीकरण

विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 2016 के पश्चात् अपनी एटलस विधि के माध्यम से विकसित, विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की है -

- **निम्न आय** - जिस देश की प्रतिव्यक्ति आय 995 डॉलर से कम हो।
- **निम्न-मध्यम आय** - जिस देश की प्रतिव्यक्ति आय 996 से 3895 डॉलर हो।
- **उच्च-मध्य आय** - जिस देश की प्रतिव्यक्ति आय 3896 से 12055 डॉलर हो।
- **उच्च आय** - जिस देश की प्रतिव्यक्ति आय 12055 डॉलर से अधिक हो।

भारत की प्रतिव्यक्ति आय के अनुसार इसे निम्न-मध्यम आय श्रेणी के देशों में शामिल किया गया है।

❖ विश्व के साथ संबंधों के आधार पर

- **बंद (Closed)**

ऐसी अर्थव्यवस्था, जो शेष विश्व के साथ संबंधों के प्रति उदासीन है या आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए विश्व के साथ संबंधों को हतोत्साहित करती है। यह संरक्षणवाद पर बल देती है।

- **खुली (Open)**

यह संरक्षणवाद की बजाय प्रतिस्पर्धा पर बल देती है। यह शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करती है, जिसमें वस्तु, सेवा, पूंजी, निवेश और तकनीक के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती है।

नोट – वर्तमान में भारत को विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

❖ अन्य आधार

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व एवं तृतीय विश्व देशों के रूप में भी किया जाता है।

- **प्रथम विश्व के देश**

अमेरिका समर्थित देशों का समूह, जो नाटो (North Athlantic Treaty Organisation - NATO) के सदस्य थे एवं यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। इसमें अमेरिका के साथ मुख्यत: पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे।

- **द्वितीय विश्व के देश**

रूस समर्थित देशों का समूह, जहां पर मार्क्सवादी विचारधारा एवं समाजवाद की अवधारणा थी। इसमें रूस, चीन, क्यूबा आदि ऐसे देश शामिल थे, जहां पर राज्य का नियंत्रण सर्वोपरि था।

- **तृतीय विश्व के देश**

शीत युद्ध के समय पूरा विश्व लगभग दो समूहों में बंट गया था। एक तरफ अमेरिका जैसी पूंजीवादी राष्ट्र थे, तो दूसरी तरफ रूस जैसे समाजवादी राष्ट्र। दोनों ही प्रकार के राष्ट्र स्वयं को शक्तिशाली दिखाने हेतु हथियारों की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ऐसे समय में जो राष्ट्र नवस्वाधीन थे, वे हथियारों की हौड़ से बचते हुए अपना विकास करना चाहते थे। अत: इन राष्ट्रों ने उपरोक्त दोनों राष्ट्रों का समर्थन न कर गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। इस संगठन में शामिल देशों को ही तृतीय विश्व के देश कहा जाता है।

❐ आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण (Classification of Economic Activities)

प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मानव के वे तमाम क्रिया-कलाप, जो आय सृजन में सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी मानव क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन, लाभ अथवा आय अर्जन करना होता है, उन्हें आर्थिक गतिविधियां या क्रिया की संज्ञा दी गई है। पारंपरिक रूप से इन आर्थिक क्रिया-कलापों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है, यथा – प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में 02 और क्षेत्रक परिकल्पित हो गए हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में बांटा गया है –

❖ प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

इसके अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों (Natural Resources) के प्रत्यक्ष दोहन (Direct Utilization) द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक वस्तुएं (Primary Goods) तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्नता को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।

❖ द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रिया-कलापों को शामिल किया जाता है, जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन या प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उसका मूल्यवर्धन (Value Addition) कर देते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण (Construction), विनिर्माण (Manufacturing) और प्रसंस्करण (Processing) से संबंधित गतिविधियां आती हैं। इसमें औद्योगिक उत्पादन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाता है।

❖ तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों का संबंध सामान्यत: सेवा गतिविधियों से जुड़ता है, जिनमें मानव की मानसिक श्रमशक्ति की अहम भूमिका होती है। परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) इसके अंतर्गत आते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र से इस मायने में भिन्न है कि वहीं द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में तकनीक, मशीन व उत्पादन प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है, सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता सेवाप्रदाता की कुशलता, विशेषज्ञता, अनुभव एवं ज्ञान पर निर्भर करती है।

❖ चतुर्थक क्षेत्र (Quartenery Sector)

इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से संबद्ध गतिविधियां अनुसंधान व विकास (R & D) पर केंद्रित होती है। इसकी परिकल्पना म्यूचअल-फण्ड प्रबंधकों से लेकर कर-परामर्शदाताओं और साफ्टवेयर सेवाओं की मांग में होने वाली वृद्धि व इसके बढ़ते महत्व के आलोक में की गई।

❖ पंचक क्षेत्र (Quianry Sector)

इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर निर्णय-प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से संलग्न लोग उस संस्थान पर शीर्ष पर मौजूद होते हैं। नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में इनकी भूमिका के मद्देनजर इनका महत्व कई अधिक होता है। इन्हें **गोल्ड-कॉलर जॉब** के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ व्यवसायिक अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, विधि व वित्त परामर्शदाताओं आदि को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत ई-लर्निंग, बौद्धिक संपदा संस्थान, विधि व्यवसाय, बैंकिंग क्षेत्रक आदि को शामिल किया जाता है।

❒ उत्पादन के साधन (Means of Production)

एक उत्पादक को किसी वस्तु के सेवा या उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। सामान्यत: उत्पादन के साधनों को 04 भागों में बांटा जाता है -

❖ भूमि (Land)

भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इससे तात्पर्य भौतिक वस्तुओं, जैसे - मकान, दुकान, खान, खेत, वन, नदी, पर्वत आदि से हैं। जब इसे उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके प्रतिफल के रूप में **लगान/किराया (Rent)** देय होता है। दूसरे शब्दों में भूमि के प्रयोग के बदले दी जाने वाली कीमत को लगान कहते हैं।

❖ श्रम (Labour)

श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम से अभिप्राय मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक कार्यों से है, जिसका प्रयोग वह धन अर्जित करने हेतु करता है। श्रम के प्रयोग के लिए दिए जाने वाले प्रतिफल को **मजदूरी (Wages)** कहते हैं।

❖ पूंजी (Capital)

पूंजी उत्पादन सर्वाधिक गतिशील साधन है। सरल शब्दों में पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित आय का वह भाग है, जिसका उपयोग अधिक मात्रा में धन उत्पादन करने हेतु किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की सेवाओं के बदले पूंजीपति को जो प्रतिफल प्राप्त

होता है, उसे **ब्याज (Interest)** कहते हैं।

❖ उद्यम/साहस (Enterprise/Risk)

जो उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम व अनिश्चितता को सहन करता है, वही उद्यमी/साहसी कहलाता है। उसे जोखिम उठाने के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे **लाभ (Profit)** कहते हैं।

साधन लागत – उत्पादन के समस्त साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का कुल योग साधन लागत कहलाती है।

साधन लागत = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ

कृषि
Agriculture

- परिचय
- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता
  - राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा
  - भारतीय कृषि रोजगार आपूर्तिकर्ता क्षेत्र के रूप में
  - कृषि क्षेत्र खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में
  - कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चा माल के प्रदाता के रूप में
  - कृषि, गरीबी उन्मूलन तथा समावेशी विकास
  - कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है
  - कृषि क्षेत्र का निर्यात में योगदान
- भारतीय कृषि की विशेषताएं
  - आजीविका का मुख्य साधन
  - छोटी जोतें
  - निम्न उत्पादकता
  - अदृश्य बेरोजगारी
  - खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता
  - परंपरागत एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति
  - निर्वाह कृषि
- फसल एवं उसके प्रकार
- योजनाकाल के दौरान भारतीय कृषि नीति एवं प्रवृत्ति : एक समीक्षा
  - हरित क्रांति के पूर्व का काल
  - 1966-80 हरित क्रांति का आगमन एवं प्रथम चरण
  - हरित क्रांति
  - 1981-1990 हरित क्रांति का प्रसार एवं द्वितीय चरण
  - 1991-2004 उदारीकरण की संध्या से उसका प्रसार
  - 2004 के पश्चात् लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं कृषि
  - वर्तमान परिदृश्य
- भारत में कृषि से संबंधित मुद्दे
  - प्राकृतिक कारण
  - अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं
  - छोटा जोत आकार
  - कृषि अनुसंधान की जानकारी अभाव
  - कृषकों की ऋणग्रस्तता
  - मध्यस्थों की अधिकता
  - बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत
  - उत्पादन की पिछड़ी तकनीक
  - क्षेत्रीय विषमताएं
- कृषि को बढ़ावा देने के लिए एवं समस्या के समाधान के लिए किए गए कार्य एवं पहल
  - अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग
  - उर्वरक एवं रासायनिक खाद का प्रयोग
  - सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
  - खेती के यंत्रीकृत साधन
  - भूमि संबंधी समस्या
  - मध्यस्थों का उन्मूलन
  - लगान का नियमन
  - चकबंदी
  - भूमि की उच्चतम सीमा
  - कृषि वित्त
  - कृषि विपणन
  - कृषि बीमा
  - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
    - प्रारंभ
    - उद्देश्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- वसूली मूल्य
- निकासी मूल्य

❖ किसान क्रेडिट कार्ड

- प्रारंभ
- उद्देश्य
- प्रमुख विशेषताएं

❖ कृषि अवसंरचना निधि

❖ तात्कालिक कृषि बिल मुद्दा - नवीन कृषि सुधार - तीन नए कृषि अधिनियम

❖ किसान उपज व्यवहार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

❖ किसान समझौता (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अधिनियम, 2020

❖ आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

❖ आलोचनाएं

- निष्कर्ष

❖ भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य

❒ अभ्यास प्रश्न

कृषि
Agriculture

❐ परिचय (Introduction)

- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग-धंधा ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की आधारशिला है।
- ❖ कृषि के संदर्भ में पं. नेहरू ने कहा था - "ज्यादातर चीजें, कृषि को छोड़कर, इंतजार कर सकती हैं।"

- जवाहरलाल नेहरू

आशय है कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के आवश्यकता है। यदि कृषि असफल रहती है, तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही असफल रहते हैं। जनगणना-2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 69% लोग गांवों में रहते हैं तथा कुल श्रमशक्ति का लगभग 55% भाग कृषि पर निर्भर है, जो वर्तमान में भी लगभग 43% बना हुआ है। कृषि खाद्यान्न तथा कच्चा माल प्रदान करने, रोजगार उपलब्ध कराने, निर्यात बढ़ाने आदि के रूप में महत्वपूर्ण होती है। भारतीय कृषि परंपरागत रूप से मानसून पर निर्भर है। फसल विविधता का एक बड़ा हिस्सा भारत में पाया जाता है। एक विशाल भौगोलिक भारत में विभिन्न फसल प्रतिरूप देखने को मिलते हैं।

❐ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता (Importance of Agriculture in Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता एक आयामी न होते हुए बहुआयामी है, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों में समझ सकते हैं -

❖ राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा

- स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।
- CSO द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1950-51 में कृषि का हिस्सा 55.4 प्रतिशत था, जो उदारीकरण की पूर्व संध्या पर 38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.65 प्रतिशत था।
- उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है, किंतु इसके बावजूद एक बड़ा भाग देश की राष्ट्रीय आय को कृषि से प्राप्त होता है।

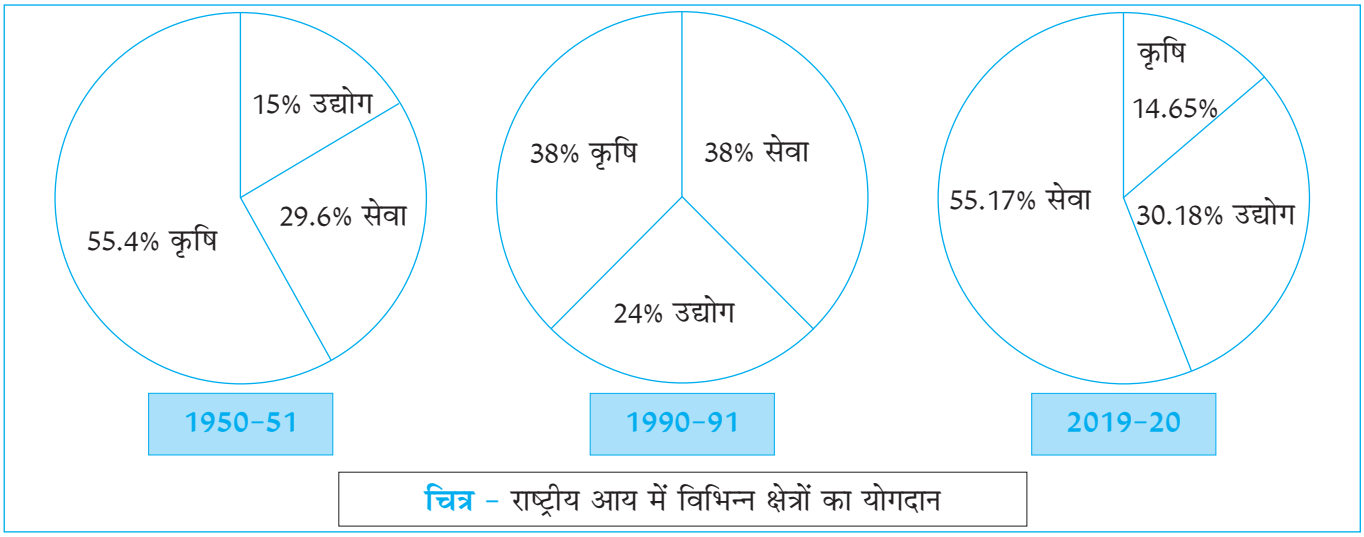

चित्र - राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

- वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के प्रभावों से जहां उद्योग एवं सेवा में नकारात्मक वृद्धि देखी गई कृषि क्षेत्र में लगभग 3.4% की सकारात्मक वृद्धि सराहनीय रही।

❖ भारतीय कृषि रोजगार आपूर्तिकर्ता क्षेत्र के रूप में

- जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 में कुल मुख्य श्रमिकों (Main Workers) का 55 प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्रियाओं में कार्यरत था।
- वर्तमान में यह लगभग 43 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय आय में घटती हिस्सेदारी के बावजूद भारत में कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला आय का स्त्रोत बना हुआ है।

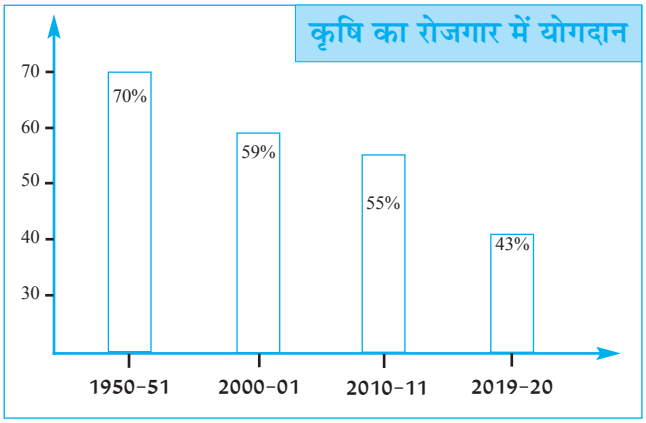

❖ कृषि क्षेत्र खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में

- कृषि क्षेत्र समस्त राष्ट्र को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हरित क्रांति के बाद के वर्षों में भारत खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो गया।
- इस प्रकार कृषि क्षेत्र ने भारत की विदेशों पर निर्भरता को कम किया एवं बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाया। 1950-51 से 2011-12 तक जनसंख्या वृद्धि 36 करोड़ से 121 करोड़ हो गई, जो 3 गुना थी।
- समान अवधि में खाद्यान्न उत्पादन 5 गुना से भी अधिक था। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2020-21 के अनुसार देश के कुल खाद्यान का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा।
- पिछले दशकों में लगातार हमने न केवल अपनी वर्तमान खाद्य आवश्यक्ताओं को पूरा किया है बल्कि आपातकाल हेतु बफर स्टॉक की व्यवस्था भी की है।

❖ कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चा माल के प्रदाता के रूप में

- कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में भाग लगभग 21.2 प्रतिशत है, कृषि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- रंगराजन के अनुसार कृषि में 1 प्रतिशत परिवर्तन आने पर औद्योगिक उत्पादन 0.5 प्रतिशत परिवर्तन आता है। कृषिगत पदार्थों का फूड प्रोसेसिंग उपयोग में भी महत्वपूर्ण योगदान है।
- आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार रिकॉर्ड 9.99% की दर से वृद्धि कर रहा है।
- अनुमान है कि भारतीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग का आकार भविष्य में और अधिक विस्तृत होगा। सूती तथा पटसन उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बागान उद्योग ये सभी कृषि पर सीधे निर्भर हैं, अन्य उद्योग जैसे - हाथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि सूक्ष्म एवं मझौले (MSME) उद्योग कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं।
- यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे विनिर्माण उद्योग उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत MSME द्वारा प्रदान किया जाता है।

❖ कृषि, गरीबी उन्मूलन तथा समावेशी विकास

- चूंकि भारत की लगभग 69 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है एवं 49 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर करती है, अत: कृषि के विकास के बिना गरीबी हटाओं एवं समावेशी विकास के नारे अधूरे हैं।
- यहां कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पंजाब व हरियाणा के अध्ययन बताते हैं कि वहां राज्य GDP में कृषि का योगदान 45 प्रतिशत से ज्यादा है और गरीबी एवं असमानता दोनों कम है।

❖ कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है

- भारत गांवों का देश है, जहां जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं